मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर महन्त रामदास का सत्कार किया

उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया व परिसर में वृक्षारोपण किया

डीग/भरतपुर/जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरूवार को डीग के पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पंचामृत से अभिषेक तथा सपत्नीक पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया तथा मंदिर परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा में मुकुट मुखारविंद पर श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने भरतपुर में बड़ा हनुमान मंदिर के पास जन सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को अभिजनों की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया।

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने भरतपुर के सेवर में लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए। गुरू वंदन कार्यक्रम के तहत, मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर में महंत रामदास महाराज का सत्कार-सम्मान किया। उन्होंने महंत को सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरू वंदन संदेश भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की।

मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर परिसर के समीप जनसुनवाई भी की, जिसमें उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुना तथा अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगत सिंह, बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी सहित, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

10 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती की रिपोर्ट गलत ठहराई रुस ने

मास्को, 10 जुलाई। रूस के श्रम मंत्रालय ने आज उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वह 2025 के अंत तक भारत से 10 लाख श्रमिकों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। मॉस्को टाइम्स ने यूराल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन के हवाले से कहा था कि भारतीय कामगारों के आने से देश में श्रमिकों की कमी दूर होगी। इस बीच रूस के उद्योगपतियों और उद्यिमयों के संघ ने भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल बनाने का विचार पेश किया है ताकि विशेष रूप से रूसी रोज़गार बाज़ार के लिए कामगारों को तैयार किया जा सके। श्रम मंत्रालय ने बाद में आरबीसी समाचार वेबसाइट को बताया कि भारत से कामगारों की भर्ती कोटा द्वारा नियंत्रित होती है जो क्षेत्रों और नियोक्ताओं की ज़रूरतों के आधार पर एक साल पहले निर्धारित किया जाता है।

- **रुस के श्रम मंत्रालय ने कहा कि भारत से मजदूरों की भर्ती का कोटा होता है जो नियोक्ता व क्षेत्र की जरुरत के आधार पर तय होता है।**

'गुजरात में सड़क, पुल, बांध टूटना आम हो गया, जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है'

कांग्रेस ने वडोदरा पुल हादसे को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की

- **कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी, सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, पिछले 16 मामलों में जांच टीम गठित हुई पर नतीजा शून्य रहा।**
- **कांग्रेस नेताओं ने कहा, गुजरात सरकार ने तय कर लिया है दुर्घटना का हिस्सा बनिए, चार लाख रु. का मुआवज़ा लीजिए। यहां जान की कीमत मात्र 4 लाख रु. है।**

नयी दिल्ली, 10 जुलाई। कांग्रेस ने गुजरात में पुल ढ़ हने से कई लोगों के मारे जाने की घटना को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा है कि राज्य में चरम भ्रष्टाचार के बीच वहां 'चंदा दो-धंधा लो' की व्यवस्था चल रही है और अधिकारी लापरवाह हो गये हैं इसलिए रोड, पुल, कैनाल, डैम टूटना, अग्निकांड की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनकी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है।

गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी एवं सेवादल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने गुरुवार को यहां कांग्रेस के नये मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार तुरंत जांच शुरु करवा देती है, लेकिन परिणाम शून्य रहता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस तरह के पिछले 16 मामलों में जांच के लिए ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित नहीं करती है तो सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा गृहमंत्री हर्ष रमेश संघवी के इस्तीफे की मांग की जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक मीडिया और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का दबाव रहता है, तब तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर लीपा-पोती की जाती है और छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन भाजपा से जुड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। गुजरात सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्रदेश भर में पिछले कुछ साल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं।

कांग्रेस नेताओं ने गुजरात में हाल में हुई दुर्घटनाओं का विवरण देते हुए कहा कि करीब तीन साल पहले मोरबी में सरकार की लापरवाही से 135 लोगों की जान चली गई। राजकोट में जनता ने चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया आखिर में गेमिंग जोन में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। वडोदरा में नाव पलटने से बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले डीसा की एक फैक्ट्री में आग लगने से करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी।

गुजरात सरकार ने मानो तय कर लिया है कि दुर्घटना का हिस्सा बनिए, जान दीजिए और चार लाख रुपए का मुआवजा ले जाइए- यानी यहां आम जनता की जान की कीमत मात्र चार लाख रुपए है।

इण्डिया गठबंधन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के लिए दबाव डालता रहेगा।

कानूनी विशेषज्ञों ने भी चुनाव आयोग के इस कदम पर सवाल उठाए हैं और यह तर्क दिया है कि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाला इतना बड़ा पुनरीक्षण - वह भी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले - सन्देह पैदा कर सकता है तथा कई लोगों को मतदाता सूची से निकाले जाने और संभावित हेरफेर का कारण भी बन सकता है। पहले कल्याणकारी योजनाओं में लगे जिला अधिकारियों को अचानक इस पुनरीक्षण कार्य में लगा दिया गया, जिससे राज्य तंत्र के दुरुपयोग और शासन में अव्यवस्था की आलोचना हुई है। अब, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने संज्ञान में ले चुका है, तो गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। यदि आयोग अपने कार्यों को संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप नहीं करता, तो विपक्ष ने चेतावनी दी है कि आयोग को कानूनी और ज़मीनी -दोनों स्तरों पर व्यापक जनविरोध का सामना करना पड़ सकता है।

कनिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेपर लीक के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसओजी ने अब तक इस मामले में 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

वडोदरा हादसे के बाद एक्शन में गुजरात सरकार

वडोदरा, 10 जुलाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुरुवार को वडोदरा में महिसागर नदी पर बीते दिन पुल के ढ हने के सिलसिले में राज्य के सड़क एवं भवन विभाग के चार इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग अब भी लापता हैं। सड़क एवं भवन विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री पटेल ने विशेषज्ञों से पुल की मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर चारों इंजीनियरों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए लोगों में कार्यकारी अभियंता एनएम नायकवाला, उप कार्यकारी अभियंता यूसी पटेल और आरटी पटेल के साथ-साथ, सहायक अभियंता जेवी शाह शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इस घटना के मद्देनजर राज्य के अन्य पुलों का तुरंत गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

- **चार इंजीनियर सस्पेंड किए, अन्य पुलों का तत्काल निरीक्षण करने के आदेश दिए।**

ज्ञातव्य है कि बुधवार सुबह वडोदरा के पादरा कस्बे के पास गंभीरा गांव के पास आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाले चार दशक पुराने पुल का एक हिस्सा ढह जाने से कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए थे।

वडोदरा जिले के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने दिन में बताया, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीन से चार लोग अभी भी लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है।

लॉ कॉलेज दुष्कर्म केस, सरकार ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

कोलकाता, 10 जुलाई। दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट कोलकाता पुलिस की तरफ से की जा रही जांच के आधार पर तैयार की गई है और इसे सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा गया। न्यायमूर्ति सौमेंद्र सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने पुलिस की केस डायरी को भी देखा और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह बाद जांच में हुई आगे की प्रगति की नई रिपोर्ट पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इस मामले में अदालत ने कहा कि पीड़िता के परिवार के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति दी जा सकती है।

- **प.बंगाल सरकार ने पुलिस जांच की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की, कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया है।**

गुरु पूर्णिमा पर दो छात्रों ने गुरु की हत्या की

हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव में प्रधानाचार्य की चाकू मार कर हत्या की

हिसार, 10 जुलाई। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुवार को हरियाणा के हिसार के बास बादशाहपुर गांव में स्थित करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात के तहत स्कूल के प्रधानाचार्य जगबीर सिंह की दो छात्रों ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

- **पुलिस को स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है। इसमें दोनों आरोपी छात्र वारदात के बाद भागते नज़र आ रहे हैं। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। अभी दोनों फरार हैं।**

इस घटना ने स्कूल परिसर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वारदात के बाद दोनों छात्र वहां से फरार हो गये। जिस वक्त यह वारदात हुई, उस समय स्कूल में पेपर चल रहा था। घायल प्रधानाचार्य को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाये। पुलिस को वारदात में शामिल चाकू मौके पर ही पड़ा मिला है। स्कूल स्टाफ ने बताया, यह बिल्डिंग नारनौंद के पूर्व विधायक सरोज मोर के परिवार की है। इस बिल्डिंग को जगबीर सिंह ने दो साल पहले लीज पर लिया था। अचानक हुए हमले से जगबीर सिंह ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन छात्रों ने उन पर चाकुओं से वार करना जारी रखा। कुछ ही सेकेंड में शरीर पर कई वार किये। इससे जगबीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों आरोपी छात्र चाकू लहराते हुए वहां से भाग गये। वहां मौजूद टीचर और अन्य स्टाफ ने तुरंत घायल जगबीर को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गयी। उधर, घटना के बाद स्कूल की भी छुट्टी कर दी गयी। पेपर दे रहे बच्चों को घर भेज दिया गया।

सूचना मिलते ही थाना बास पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक जगबीर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एक टीम स्कूल भी भेजी गयी, जिसने घटना के बारे में स्कूल स्टाफ और छात्रों से जानकारी ली। 'सीन ऑफ क्राइम' टीम ने भी मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाये।

थाना बास प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आयी है। इसमें दोनों आरोपी छात्र वारदात के बाद भागते हुये नजर आ रहे हैं। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली है। उन्हें पकडऩे के लिए टीमें लगायी गयी हैं। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है।

पुलिस ने अभी तक जो जांच की है, उसमें सामने आया है कि प्रिंसिपल जगबीर सिंह स्कूल के सभी छात्रों को अपने बाल छोटे रखने के लिए कहते थे। जिन दोनों लडक़ों पर हत्या करने का आरोप लगा है, उन्हें भी टोकने की बात सामने आयी है। इसके अलावा, एक आरोपी की उम्र करीब 16 साल है, जो कक्षा 11 का छात्र है, जबकि दूसरे की उम्र 17 साल है, जो 12वीं का छात्र है। दोनों की पहले भी शरारत करने की शिकायतें होती रही हैं, लेकिन अध्यापकों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था।

'हमने ''उदयपुर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खुलेगी, तब वह फिर से इसका उल्लेख करें।

दिल्ली हाईकोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर इस याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर यह कहते हुए रोक लगाने की मांग की गई है कि यह सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है।

'आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दस्तावेजों को स्वीकार करने पर चुनाव आयोग को विचार करना है। द्विवेदी ने कहा कि यह आयोग के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी जिसमें तीन मुख्य सवालों पर फोकस होगा। क्या चुनाव आयोग के पास मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को शुरू करने की शक्ति है? प्रक्रिया और तरीका क्या वैधानिक रूप से उचित है? क्या इतनी कम समयावधि, जबकि नवंबर में बिहार चुनाव हैं, में इसे पूरा करना संभव है?

न्यायालय ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। आयोग को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है और प्रत्युत्तर 28 जुलाई से पहले।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन कानून आधार को मान्यता देता है। और चुनाव आयोग इसे चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि आधार का प्रबंधन गृह मंत्रालय के अधीन है, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया।

द्विवेदी ने सुझाव दिया कि मामला 2 अगस्त को सुना जाए, तब तक ड्राफ्ट सूची सामने आ जाएगी। और अगर एक करोड़ लोग छूट जाते हैं, तब कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसे अदालत में ''अपरिवर्तनीय'' के रूप में पेश किया जाएगा।

न्यायमूर्ति बागची और धूलिया ने कहा कि पूरी प्रक्रिया व्यक्ति की पहचान पर केंद्रित है। आप जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति ए है या बी। आधार इस पहचान का प्राथमिक दस्तावेज है।

जस्टिस बागची ने हैरानी जताई कि आप जिन 11 दस्तावेजों को मांग रहे हैं, वे नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए हैं फिर भी आप आधार को मानने से इनकार कर रहे हैं।

चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा कि आधार सामान्य रूप से रहने वाले गैर-नागरिकों को भी जारी होता है और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

इस पर द्विवेदी को बताया गया कि चुनाव आयोग की सूची में से कम से कम पांच दस्तावेज ऐसे हैं जो जन्म तिथि या जन्म स्थान नहीं दर्शाते - जबकि जन्मतिथि व जन्म स्थान मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता की अनिवार्य शर्तें हैं।

सिंघवी ने कहा कि आधार एक वैधानिक पहचान पत्र है, जिसे सरकार स्वयं बढ़ावा देती रही है, लेकिन अब उसे अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (1995) के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि एक बार व्यक्ति मतदाता सूची में आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी नागरिकता के संदर्भ में अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया है।

सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता कपिस सिब्बल ने बताया कि राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की केवल 14.1 प्रतिशत आबादी के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है और मात्र 2 प्रतिशत के पास पासपोर्ट है, लेकिन 87 प्रतिशत के पास आधार कार्ड है।

नाबालिग का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 01 जुलाई, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब अभियुक्त के घरवालों को बताया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं, बाद में डरा-धमकाकर राजीनामा करवा लिया। इसके बाद 27 जून को अभियुक्त उसकी बेटी को भगाकर ले गया। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को गोटन रेलवे स्टेशन से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन अभियुक्त उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। रेलवे स्टेशन के पास उसे जूस पिलाया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे दूसरे दिन गोठन गांव में होश आया। यहां अभियुक्त ने दो दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं बाद में रेलवे स्टेशन पर पुलिस आकर उसे ले गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता की माता और उसके पिता के बीच पैसों के लेन-देन का विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पिता ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी बेटी की हत्या की

गुरुग्राम में पिता ने बेटी राधिका यादव को गोलियों से भून दिया

गुरूग्राम, 10 जुलाई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाले मामले में पिता ने अपनी टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव को गोलियों से भून दिया। राधिका एक उभरती हुए प्लेयर बताई जा रही है, जिसने स्टेट लेवल पर कई खिताब जीते थे। पिता ने बेटी पर एक-एक कर पांच गोलियां दागीं, जिसमें से तीन उसे लगीं। घटना गुरुग्राम के सुशांत लोक-2 स्थित घर पर हुई। जिस बेटी ने पिता का नाम रोशन किया, वही क्यों उसका कातिल बन गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

- **राधिका यादव ने कुछ समय पहले एक टेनिस कोचिंग एकेडमी शुरु की थी। पुलिस के अनुसार पिता दीपक एकेडमी बंद करने के लिये दबाव बना रहा था। आज तीखी बहस के बाद उत्तेजित पिता ने अपनी बेटी को गोलियां मार दीं।**

जानकारी के मुताबिक पिता की गोलियों से छलनी राधिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के पीछे की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे सेक्टर 57 स्थित आवास पर हुई। राधिका अपने परिवार के साथ यहां रहती थीं। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मौके से उस रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया, जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राधिका राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थीं और कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी थीं। राधिका यादव की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च, 2000 को हुआ था और वह आईटीएफ युगल में शीर्ष 200 में थीं।पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार, दीपक यादव प्रॉपर्टी डीलर है और उनकी बेटी राधिका यादव ने क्षेत्र में एक टेनिस कोचिंग एकेडमी शुरू कर दी। इसमें काफी युवक-युवतियां कोचिंग लेने आते थे। पुलिस के अनुसार इस एकेडमी को बंद करने के लिए दीपक अपनी बेटी राधिका पर दबाव बना रहा था।

कैनरा बैंक ने अनिल अंबानी के ऋण खाते से धोखाधड़ी का आरोप वापस लिया

मुंबई, 10 जुलाई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उपक्रम केनरा बैंक ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी के 1,050 करोड़ रुपये के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत करने का अपना फैसला वापस ले लिया है।

गौरतलब है कि जून में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत किया था।

केनरा बैंक ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी इकाई को दिए गए 1,050 करोड़ रुपये के ऋण के दुरुपयोग के आरोप में संबंधित ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता के रूप में चिह्नित कर दिया था। बैंक ने कहा था कि मूल रूप से 2017 में स्वीकृत कर्ज की उस धनराशि का कंपनी ने दुरुपयोग किया गया था। बैंक ने इस आरोप में खाते को नवंबर 2024 में इसे धोखाधड़ी वाला खाता घोषित कर दिया था।

केनरा बैंक ने आरोप लगाया था अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस ने उस ऋण पर लागू मूल शर्तों का उल्लंघन किया गया और ऋण राशि को समूह की कंपनियों के साथ लेनदेन , म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों में निवेश करने धन की दूसरे कामों के लिए हेराफेरी की ।

केनरा बैंक ने आरोप लगाया, प्राप्त ऋण की राशि को को म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों में भी निवेश किया गया और संबंधित और गैर-संबंधित पक्षों को भुगतान करके इधर-उधर कर दिया।

शशि थरूर ने आपातकाल पर अपनी ही पार्टी, कांग्रेस, को घेरा

कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, आपातकाल भारत के इतिहास का काला अध्याय है इससे सबक लेना चाहिए

तिरुवनंतपुरम, 10 जुलाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को आपातकाल को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल मेंअनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरताकी गई।आपातकाल को भारत के इतिहास का महज काला अध्याय नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसके सबक को पूरी तरह से समझना जरूरी है। उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कामों को लेकर सवाल उठाए।

एक मलयालम अखबार में प्रकाशित लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए। जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता।

- **शशि थरूर ने मलयालम अखबार में छपे लेख में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए।**

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती की गई। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक बहुमूल्य विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी आपातकाल के सबक अभी भी चिंताजनक रूप से प्रासंगिक हैं।

थरूर ने कहा कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और सांविधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का प्रलोभन विभिन्न रूपों में फिर से प्रकट हो सकता है। अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है।

इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के रक्षकों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908